

(ख) मध्य प्रदेश में सप्लाई की गई बिजली का डिजीजन-बार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में सिंचाई पम्पों के लिये अगले वर्ष डिजीजन-बार कितने कितने ग्रामों को बिजली सप्लाई किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और बिजुत मन्त्रालय में उप-सत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मध्य प्रदेश में 1970-71 के दौरान 20920 सिंचाई पम्प ऊजित हुए थे ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्रम संख्या	मंडल का नाम	कृषि उद्देश्यों के लिए 70-71 के दौरान बेची गई ऊर्जा	1971-72 में विद्युतीकृत होने वाले ग्रामों की संख्या	1971-72 में ऊजित होने वाले पम्पो की संख्या
(मिलियन यूनिटो मे)				
1.	रायपुर	2.67	195	3865
2.	बिलासपुर	0.79	113	2555
3.	जबलपुर	8.29	324	6410
4.	रेवा	2.32	136	2660
5.	इंदौर	35.72	480	9500
6.	भोपाल	9.61	174	3480
7.	ग्वालियर	5.47	78	1530
	कुल	64.87	1500	30000

Eviction of Inmates from Raima Sorma, Tripura

4581. SHRI DASARATHA DEB : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether notices are being served on a large number of inmates of Raima Sorma (Tripura) to vacate land for Dumbura Hydro Electric Project ;

(b) if so, the number of families involved in this matter ; and

(c) the alternative occupation being provided to the evicted or would-be evicted families of Raima Sorma ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND PO-

WER (SHRI B. N. KUREEL) : (a) Yes, Sir, notices are being served on all persons on the lands in Raima Sorma to be submerged by Dumbura Hydro electric Project.

(b) About 300 families.

(c) Besides providing alternative land and compensation for property, Government are also trying to provide alternative means of livelihood to the evicted or would be evicted families of Raima Sorma.

जनता को बहोज प्रथा के कारण होने वाली कठिनाइयां

4582. श्री राम जगत पाखान : क्या बिबि और ग्याथ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि

“तिलक” तथा “दहेज” प्रथाओं के कारण लोगो को बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हा, तो इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार ने कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) . (क) और (ख) दहेज देने और लेने को रोकने की दृष्टि से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 बना दिया गया है।

विद्युत बोर्डों का कार्यकरण

4583. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे : क्या सिंघाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या विभिन्न राज्यों के राज्य विद्युत् बोर्डें सतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन बोर्डों के उचित कार्यकरण तथा अन्य मामलो की जाच करने के लिये वर्ष 1964 से बैकटरामन समिति गठित की गई थी ; और

(ग) यदि हा, तो उस समिति की मुख्य-मुख्य सिफारशें क्या हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंघाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) 1967-68 से 1969-70 तक के वर्षों के लिए बोर्डों की कार्यप्रणाली के वित्तीय परिव्ययो को सूचित करने वाला विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा प्राप्त किए गए औसत पूजा आधार पर लाभ दर दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [प्रन्धालय में दिया गया। देखिये सख्या LT—650/71]

(ख) बैकट रामन समिति (i) विभिन्न राज्य

विद्युत बोर्डों के राजस्व में तथा विद्युत कर से होने वाली आमदनी में वृद्धि लाने के मार्गोपाय सुझाने के लिए तथा (ii) टैरिफ और विद्युत कर के बीच सम्बन्ध की पद्धति सुझाने के लिए, 1964 में स्थापित की गई थी ;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा उचित लाभ कमाने से सबधित बैकटरामन समिति की रिपोर्टें में दी गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं और सबधित राज्यों को भारत सरकार के सकल्प सख्या ई० एल०-II-3 (i)/64, दिनांक 3 मार्च, 1965 द्वारा जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है, प्रेषित कर दी गईं। [प्रन्धालय में रखा गया। देखिये सख्या LT—650/71] इन सिफारिशों को परिष्कलना करते हुए अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डों ने, व्यवस्थित तरीके से, सुझाए गए लाभ लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य में, अपनी राजस्व आय का समायोजन करने के लिए समय-समय पर अपने टैरिफ सशोधित किए हैं। राज्य विद्युत बोर्डों ने अपने लाभ लक्ष्यों को कहा कहा तक प्राप्त किया है, केन्द्रीय सरकार इसकी जाच करती है।

U. N. O. Inter-Regional Seminar on Water Resources

4584. SHRI P. K. DEO . Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the Central Government are participating in the Inter-Regional Seminar on Water Resources to be organised by the U. N. O. for the sake of developing countries ;

(b) whether the last Seminar was held ; and

(c) the main recommendations of the Seminar ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. N. KUREEL) : (a) to (c). The hosting by the Government of India of the Inter-Regional Seminar on Water Resources to be organised by the U. N. O. is under